

Title: Regarding setting up more centres for procurement of paddy by the FCI for the peasants in Bihar.

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी) : अध्यक्ष महोदय, मेरी राजनीति की बात नहीं है, मेरी बात यह है कि अभी भारत सरकार ने पंजाब के किसानों के लिए काफी सहूलियतें दी हैं, आंध्र के किसानों के लिए भी दी हैं लेकिन बिहार की हालत ऐसी है कि वहां पहले जो धान की उपज होती थी, वह नेपाल और बंगलादेश को भी जाती थी।

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Uttamrao Dhikale, do not disturb the proceedings of the House. I will call your name also.

...(Interruptions)

श्री राधा मोहन सिंह : पिछले दो वर्षों से नेपाल और बंगलादेश में धान की अच्छी उपज होने के कारण बिहार के किसानों को ढाई सौ से तीन सौ रुपये प्रति क्विंटल तक धान बेचना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और मुख्य रूप से खाद्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय खाद्य निगम ने अभी मात्र तीस केन्द्र वहां खोले हैं और वे बिल्कुल अपर्याप्त हैं और तीस केन्द्रों में से कई ठीक प्रकार काम नहीं कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि हर जिले में कम से कम एक केन्द्र जरूर हो। (व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : एक केन्द्र से क्या होगा।

श्री राधा मोहन सिंह : यह मेरी बात है, आपको जो कहना होगा, कहिए। किसी जगह एफ.सी.आई. के बहुत केन्द्र खोले गए हैं और किसी जगह एक भी नहीं है। फिर पंजाब के समान बिहार के मामले में मानकों को शिथिल कर धान से चावल प्राप्त होने का प्रतिशत 67 के स्थान पर 64 किया जाए ताकि एक क्विंटल धान से 67 किलो के बजाए 64 किलो चावल प्राप्त होने की छूट दी जाए। पंजाब में जो मानक तय किया गया है, भारत सरकार बिहार में भी वही मानक तय करे। साथ ही केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करे कि बिहार सरकार जितना भी चावल खाद्य निगम को देना चाहे, खाद्य निगम उसे स्वीकार करे। (व्यवधान) जैसे पंजाब या आंध्र में भारत सरकार 30 प्रतिशत धान की खरीद कर रही है, 70 प्रतिशत राज्य सरकार कर रही है, मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि वह बिहार सरकार को निर्देश दे कि वह भी बिहार में इसी प्रकार की खरीदारी करे। बिहार में जो स्पर्ट जिसके विषय में कहा जा रहा है कि उसके माध्यम से, उसे भी निर्देश दिया जाए कि बिहार की सरकार खरीदारी करे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब समाप्त कीजिए।

श्री राधा मोहन सिंह : आंध्र की सरकार खरीदारी कर रही है। (व्यवधान)

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions)*

अध्यक्ष महोदय : राधा मोहन जी, अब समाप्त कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा : बिहार की स्थिति से सारी दुनिया अवगत है। (व्यवधान)

*Not Recorded.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी समाधान दे रहे हैं।

â€¦(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णािया) : वहां सरकार ठीक से तनख्वाह भी नहीं दे पाती। (व्यवधान)

मंत्री महोदय जवाब देते हैं लेकिन बिहार में कुछ नहीं हो पाता। (व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : अध्यक्ष जी, बिहार के किसानों के संबंध में यहां बहुत चर्चा हुई है। आदरणीय कृषि मंत्री जी और अन्य लोगों के साथ दो-तीन दिन तक हम बैठे हैं। मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बिहार से हमको मुख्य मंत्री महोदय का पत्र 27 नवम्बर को मिला था जिन्होंने कहा कि यहां भी फसल को कुछ नुकसान हुआ है इसलिए जिस तरह पंजाब को रिलैक्सेशन दी गई है उस तरह बिहार में भी मिलनी चाहिए। 27 नवम्बर को हमें पत्र मिला था, 30 नवम्बर को हमने अपनी टीम भेज दी, 3 दिसम्बर को वह टीम वापिस आई और उसके आधार पर हमने धान में 6 प्रतिशत रिलैक्सेशन देने का निर्णय कर दिया।

दूसरी बात, हम प्रत्येक प्रदेश के लिए लेवी प्राइस तय करते हैं। उसके आधार पर राज्य सरकार आदेश देती है और उसके आधार पर हम चावल लेते हैं। हमने बिहार के लिए 861 रुपये कॉमन के लिए, 908 रुपये ग्रेड 'ए' के लिए तय किए हुए हैं। इस आधार पर हमको चावल दिलाने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। इस आधार पर जितना चावल हमको मिलेगा, हम लेने को तैयार हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर देना

चाहता हूँ। (व्यवधान) मेरी पूरी बात सुन लीजिए। (व्यवधान) जो रेट तय किया जाता है, वह एन.एस.टी. को ध्यान में रख कर तय किया जाता है।

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions)*

श्री शान्ता कुमार : आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। यह जो रेट तय किया जाता है, यह एन.एस.डी. को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। राज्य सरकार इसका आदेश जारी करती है और आदेश के मुताबिक मिल ओनर लेकर हमको देते हैं। (व्यवधान) यह जो 861 और 908 रुपये का रेट है, इस रेट में एन.एस.डी. को लगाकर रेट तय किया गया है। इस रेट पर बिहार की सरकार जितना चावल कहे, हम ले लेंगे।

*Not Recorded.

के रूप में लेने को तैयार हैं। केन्द्र खोलने की बात कही गई है। (व्यवधान) आप भी तो बात सुना करिये। रघुवंश प्रसाद जी, मेरी बात सुनिये तो सही। 30 केन्द्र खोले जा चुके हैं। माननीय सदस्यों ने कहा कि जिस जिले में कोई केन्द्र नहीं है, वहां भी केन्द्र खोले जायें। (व्यवधान) इस सरकार ने निर्णय ले लिया कि हर जिले में कम से कम एक केन्द्र अवश्य होगा और उस केन्द्र में जितना चावल आप देंगे, एफ.सी.आई. उसको लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। (व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : कब तक होगा?... (व्यवधान)

श्री शान्ता कुमार : केन्द्र खोले गये हैं, वे अभी लेने को तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : प्रतिशत का क्या हुआ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, प्लीज। आप क्या कर रहे हैं। आपको हमने नहीं बुलाया। आपके लिए कोई नियम नहीं है क्या?

श्री शान्ता कुमार : जैसा हमें बताया, छः प्रतिशत रिलेक्सेशन वहां के किसानों की मदद करने के लिए लैबोरेट्री में सैम्पल टेस्ट करने के बाद हमने दे दी। (व्यवधान) उनकी एक और मांग थी कि क्योंकि यह रिलेक्सेशन दी है तो आउट टर्न रेश्यो में भी रिलेक्सेशन चाहिए।... (व्यवधान) आउट टर्न रेश्यो में छः प्रतिशत के कारण रिलेक्सेशन 65 प्रतिशत तक आती थी, लेकिन बिहार की विशेष परिस्थितियों को देखकर, क्योंकि वहां बड़ी मिलें नहीं हैं, यह देखकर बनता तो 65 प्रतिशत था, ... (व्यवधान) लेकिन हमने रिलेक्सेशन 64 प्रतिशत करने का निर्णय भी कर दिया है। एक और बात की वहां पर बिहार की सरकार ने हमें... (व्यवधान) आप सुन लीजिए। रघुवंश प्रसाद जी, सुना तो करिये। यह बात गलत है कि आप कहते तो रहते हैं, लेकिन सुनते नहीं हैं।... (व्यवधान) बिहार की सरकार ने हमें कहा कि हमारी 550 प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसायटीज हैं, वे सोसायटीज प्रिक्यूर करके हमें देना चाहती हैं।... (व्यवधान) हमने कह दिया कि ये 550 सोसायटीज जितना चावल देना चाहें, हम उसे आज से लेने को तैयार हैं।... (व्यवधान) फिर उन्होंने कहा कि केवल चावल नहीं, वे धान भी लेना चाहती हैं। हमने निर्णय ले लिया कि यदि 550 प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसायटीज (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing should go on record except what the Minister says.

(Interruptions)*

*Not Recorded.

श्री शान्ता कुमार : हमें चावल के साथ धान भी देना चाहती हैं तो 70-30 के रेश्यो पर हम धान भी लेने को तैयार हैं। एक और बात इसमें कही गई है। (व्यवधान) बिहार सरकार ने एक और मांग की। उन्होंने कहा कि 550 प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसायटीज को हम जो इंसीडेंटल चार्ज देते हैं, जो बाकी जगह देते हैं, वह बिहार में ठीक नहीं बैठता, (व्यवधान) क्योंकि प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसायटीज का यह सारा धान लेकर चावल बनवाकर एफ.सी.आई. तक पहुंचाने में ज्यादा खर्च आयेगा। इस बात को 15 दिन हो गये, लेकिन बिहार सरकार के अधिकारी आये, मैंने कहा कि आप स्कीम लाइये। (व्यवधान) अगर इंसीडेंटल चार्ज बढ़ाने की बात होगी तो हम उसके आधार पर इंसीडेंटल चार्ज बढ़ाने को तैयार हैं। (व्यवधान) इसे 15 दिन हो गये, लेकिन हमारे पास स्कीम नहीं आई है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, माननीय रघुवंश जी ने कहा कि उनके समय में 103 केन्द्र खोले गये थे। (व्यवधान) केन्द्र खोले थे, लेकिन 103 जो केन्द्र खोले गये, उनमें केवल 25 हजार टन धान लिया गया, जिसका चावल आज तक नहीं बना।

13.00 hrs.

अब हम नीलाम कर दें, क्योंकि धान से चावल बनाने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की थी। हम नीलाम कर रहे हैं। हमें डेढ़ करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। बिहार सरकार को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए हमने 12 लाख टन अनाज का आबंटन किया है। बिहार सरकार ने नौ लाख टन अनाज आज तक नहीं उठाया है। हम बिहार सरकार को 168 करोड़ रुपए का फूडग्रेन बिल्कुल मुफ्त मिड-डे मील के अंतर्गत देना चाहते हैं। बिहार सरकार ने 1,87,000 टन में से केवल 30,000 टन उठाया है। पिछले साल भी 2, 80,000 टन में से केवल 12,000 टन उठाया था।

अंतिम बात और कहना चाहता हूँ। हम बिहार की मदद करना चाहते हैं। दिसम्बर, 2000 तक दस महीनों के अंदर 3,98,000 टन चीनी

बिहार सरकार को आबंटित की गई। उसमें से 1,49,000 टन चीनी बिहार ने नहीं उठाई है। बिहार जितना चावल देना चाहे हमारे केन्द्रों को, हम लेने को तैयार हैं।

â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing should go on record.

*(Interruptions)**

*Not Recorded.

MR. SPEAKER: Now, Shri Uttamrao Dhikale will speak.

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको पहले प्रोसीजर मालूम होना चाहिए कि हाउस में कैसे बिहेव करना चाहिए।